भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2206

बुधवार, 12 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

इसरो का अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग

2206. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इसरो के अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों और देशों के साथ सहयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार किसी आगामी मिशन के लिए विदेशी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी निवेश और अंतरिक्ष संबंधी कार्यकलापों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(घ) अंतरिक्ष अन्वेषण एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति में योगदान देने वाले अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में इसरो का ध्येय क्या है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

****

(क) वर्तमान में 61 देशों और पांच बहुपक्षीय निकायों के साथ अंतरिक्ष सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र उपग्रह सुदूर संवेदन, उपग्रह नौवहन, उपग्रह संचार, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहीय अन्वेषण तथा क्षमता निर्माण हैं।

(ख) जी, हां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) के साथ मिलकर 'निसार (नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार)' नामक एक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने के लिए काम कर रहा है, जो साकार होने के अग्रिम चरणों में है। इसरो सीएनईएस (फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी) के साथ मिलकर 'तृष्णा (उच्च विभेदन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन हेतु तापीय अवरक्त प्रतिबिंबन उपग्रह) नामक एक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने के लिए काम कर रहा है, जो प्रारंभिक चरणों में है। इसरो और जाक्सा (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी) ने संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को साकार करने के लिए संभाव्यता अध्ययन किए हैं।

..2/-

(ग) सरकार ने भारत में निजी क्षेत्र निवेश, उनकी भागीदारी और अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

I. अंतरिक्ष क्षेत्र को उदार बनाया गया है और निजी क्षेत्र को आद्योपांत अंतरिक्ष गतिविधियाँ आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

II. अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्राधिकृत करने और उनका निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष विभाग में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) का गठन किया गया था।

III. सरकार ने एक संपन्न अंतरिक्ष परितंत्र बनाने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियामक निश्चितता प्रदान करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 तैयार की है।

IV. निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और उन्हें ठोस सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इन-स्पेस द्वारा बीज निधि योजना, मूल्य निर्धारण सहायता नीति, परामर्श सहायता, तकनीकी केंद्र, एनजीई के लिए डिजाइन लैब, अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास, इसरो सुविधा उपयोग सहायता, एनजीई को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतरिक्ष परितंत्र के सभी हितधारकों से जुड़ने के लिए इन-स्पेस के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का सृजन आदि जैसी विभिन्न योजनाओं की भी घोषणा की गई और उन्हें कार्यान्वित किया गया।

V. इन-स्पेस द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय दृष्टिकोण और रणनीति की भी घोषणा की गई है, जिससे समग्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

VI. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए ₹1000 करोड़ की उद्यम पूंजी (वीसी) निधि की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

VII. गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) द्वारा परिकल्पित अंतरिक्ष प्रणालियों और अनुप्रयोगों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इन-स्पेस ने ऐसी गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) के साथ लगभग 78 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे प्रमोचन यानों और उपग्रहों के निर्माण में उद्योग की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

VIII. भारतीय एनजीई की विदेशी पूंजी तक पहुंच को आसान बनाने हेतु भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए संशोधित एफडीआई नीति जारी की है।

IX. इन-स्पेस ने सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत भू प्रेक्षण (ईओ) प्रणाली की स्थापना शुरू की है। गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) से अभिरुचि की अभिव्यक्ति

(ईओआई) आमंत्रित की गई है। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया है।

X. भारतीय कंपनियों को लघु उपग्रह प्रमोचन यान (एसएसएलवी) से संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है और चुने गए बोली लगाने वालों से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है।

XI. एनजीई को भारतीय कक्षीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इन-स्पेस द्वारा अवसर की घोषणा की गई है। एक भारतीय कंपनी का चयन किया गया है।

(घ) इसरो अपने कार्यक्रम संबंधी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने, अंतरिक्ष विज्ञान और भू-प्रेक्षण डेटाबेस में वृद्धि करने, भू-केंद्र नेटवर्क का विस्तार करने, संयुक्त प्रयोगों के माध्यम से उत्पादों तथा सेवाओं को बेहतर बनाने एवं विशेषज्ञता के प्रवाह हेतु मंच स्थापित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सहयोग का अनुसरण कर रहा है।

****